of India should not have exercised control over the utilisation of grant. It may be a grant but it is still money. This grant may have been utilised for some other purpose.

SHRI MADHAVRAO SC1NDIA: Let me first correct the impression of the hon. Member. I do. net know if my hon. Minister of State used the word 'no other option. If he did, he obviously meant there may have been other options but this was an outright grant. We were not spending any money at all except the 5 million pounds that we were going to spend on some spares. Apart from that, we are not spending any money. I think, in that context, what the Minister meant when he used the words 'no option' was not that other alternatives were not available to us, but then the outflow would have been much later. As far as what the hon. Member asked about the alleged reckless use of the grant is concerned, there were two committees which went into this and did clear it on technical parameters and also the economic parameters Whatever the differentiation there was on the economic parameters of operation, that was compensated by the 10 million pounds that was given again as an outright grant against operational loss. Therefore, there were two Committees which had cleared this helicopter subsequently.

श्री मोहम्मद सलीम: समापिन महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा अपने एतर में कराशा कि यह हमें बाहर से अनुदान के तौर पर मिला था। लेकिन यह भी पक्षन हंस के लिए लायबिलिटीज बना है। जो फौरेन एक पर्वेज दिया गया था बैस्टलैंड खरीदने के लिए एमफे लिए प्रवक्त हंस को नाफी इक्षित्र करना पड़ा गवर्नमेंट के एक उंदे में और वह पूरा नहीं कर पायें, उसके लिए अपने हंस बुद-ब-खुद सूखा जा रहा

है, मरा जा रहा है। मैं प्रश्न पूछना चाइता हूं संजी भहत्यण से कि उन्होंने भार्ट-की के जनका में यह कहा है कि.—

"The foreign exchange cost of acquisition of 21 helicopters, spare engines, ground support equipment and engine test bed was 70 million pounds equivalent to Rs. 141.53 crores."

जो. श्विनिश्चयल कान्ट्रेक्ट का उसके मुताबिक इनिश्चित रैकेज साँफ स्पेप्स तमाम के साथ दिये, लेकिन उस व्यक्त औ एटोिएयेट किया गया था स्पेप्स के लिए उसके बाकजूद बाद के यह वेका गया कि सह स्पेप्स के लिए उसके बाकजूद बाद के यह वेका गया कि सह स्पेप्स के ही है और प्राउद्धिक वारमां पड़ रहा है, तं बाद में स्पेप्स स्पेप्स व्यक्त एका उस के कान्या के स्पेप्स व्यक्त एका उस के कान्या स्पेप्स वा सौर यह किया के सन्यान समिला वा सौर वह किया के सन्यान समिला वा सौर वह किया वा स्पेप्स वा सौर वह किया वा सौर वह किया वा सौर वह किया वा सौर वह किया वा सौर वह कीन वा सौर किया वा सौर वह कीन विकास के सिलाकोंने वा सौर वह कीन विविद्या के स्पेप्स वा सौर वा सीर का सीन वा सीर वा सीर वा सीर कीन वा सीर वा सीर कीन कीन वा सीर की सीर की सीर कीन वा सीर की सीर कीन वा सीर

श्री संख्य राव सिंधवा : सर, आज का तो सकल ही नहीं उठता । अभी अंध्र राइट गरंटी था तो आज का तो सकल ही नहीं उठता । जो पूरा एमाउंट हाण 65 मिलियन पींड का मीर 10 मिलियन पींड आपरेशनस सोस के एगेंस्ट, वह तो माउट र इट गारंटी था, उस पर कोई आज तो या नहीं । जहीं तक स्पेंग्में का सबाल है, मानरेदिक मेंबर कलमाडी सहव ने भी गह बात पूछी थी, उसके बारे में मैं पूरे डिटेस्ट जो भी मणी तक माउट पलो हुमा है, हर एक डिटेस्ट में मेंम्बर्स को टेने के लिए तैगर हूं मगर कह कर सहते हैं।

# Coal supply to power plants In Madhya Pradesh

- \*3. SHRI SURESH PACHOURI: Will, the Minister of COAL be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the State of Madhya Pradesh is not be-

ing supplied the requisite quantity of coal for its power plants and for domestic and industrial consumption by the concerned coal mines;

- (b) if so, what are the reasons therefor; and
- (c) what action Government propose to take to augment the coal supply to the State of Madhya Pradesh?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDAR): (a) to (c): A statement is laid on the Table of the House

### Statement

(a) and (b) There has been some shortfall in supply of coal to indus-

trial and domestic consumers because more coal had to be made available to higher priority core sectors like power, cement, steel and railways. As regards supply of coal during last four months, to six Thermal power stations located in Madhya Pradesh, the details are given in Annexure. (See below)

(c) All out efforts are being made to increase supply of coal to core sector. As regards non-core sector, Ministry of Coal has issued instructions to coal companies to supply at least 50 per cent of the linked quantity of coal to them by rail or by road. These measures are expected to augment supply of coal to all consumers including the consumers in the State of Madhya Pradesh

#### Annexure

SLC Linkage, Receipts consumption and doing stock of coal at the Thermal Power Stations in Madhya Pradesh for the month oj April to July, 1991.

(Fig. in '000 tonnes)

SI. Name of T.P.S. No.	Particulars	April, 1991	May, 1991	June, 1991	July, 19 <b>91</b>
1 2	3	4	5	6	7
1. Amarkantak	. Lipkage	120	120	120	120
	Receipts	102	77	47	66
	Consumption	79	85	62	47
	Stocks (Days)	75(19)	68(17)	53(13)	69(17)
2. Koriba East	Linkage	210	210	210	180
	Receipts	149	117 .	159	118
	Consumption	155	115	157	117
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Stocks (Days)	101(14)	106(15)	98(14)	107(18)
3. Korba West .	· Linkage	330	330	330	330
	Receipts	267	278	285	227 `
	Consumption	313	264	249	296
	Stocks (Days)	73(7)	89(8)	138(13)	68(6)

1 2	3	4	5	6	7
4. Satpur	Linkage	400	400	400	350
	Receipts	289	279	295	328
	Consumption	311	302	272	300
	Stocks( Days)	9(1)	2(Nil)	24(2)	40(3)
5. Korba STPS( NTPC)	. Linkage	750	750	750	750
	Receipts	741	702	688	750
	Consumption	781	739	692	761
	Stocks (Days)	127(5)	106(4)	112(4)	88(4)
6. Vindhyachal (NTPC)	Linkage	- 390	390	390	390
	Receipts	281	163	241	263
	Consumption	316	282	247	287
	Stocks (Days)	120(9)	96(7)	96(7)	70(5)

श्री सरेश पश्रीरी : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की कोल वेगंस का जो कोटा है वह राज्य की आवश्यकता की देखते हुए बहुत कम है ग्रीर पर्याप्त माला में कोयला मध्य प्रदेश को उपलब्ध न होने की वजह से मध्य प्रदेश ग्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुमा है । साथ ही वहाँ के उपभोक्ता भी बहुत परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहंगा कि प्रदेश को वास्तव में कितना कोयला ब्राबंटित किया गया कितना कोयला ढुलाई किया गया, बास्तविक मांग, ग्राबंटन तथा ढ्लाई का प्रतिशत पिछले तीन वर्षी में क्या है ? "ख" पार्ट--मध्य प्रदेश को पूर्ण कोटा होने के लिए कितने वैगंस की ग्रावश्यकता है तथा ग्रभी तक कितने वेगंस ग्राबंटित किए गए हैं ? इसका तीसरा भाग है---क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत पूरानी माइंस हैं, इसलिए क्या मध्य प्रदेश में कोयला मापूर्ति की वृद्धि करने के लिए डब्ल्य० सी एल के ग्रंतर्गन कभी माइत्स खोली जायेंगी ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी ग्रीर उनमें कितना प्रीडक्शन मिलेगा, क्योंकि हाल

महाकोशल शीजन में डीलिंग हुई है, उसके क्या परिणाम निकले हैं, यह मैं माननीय भंजी महादय से जानना चाहता हूं।?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA).- Sir, as far as the availability of wagons is concerned, there is an overall shortage, in the whole of the country. It is not confined to the State of Madhya Pradesh only. We are trying to improve the availability. We are in constant touch with the Railways.

In regard to the allotment, we do not allot it in terms of States. It is done only in terms of sectors like power, cement, steel and other consumers. Unfortunately, I do not have that figure with me. All these figures have to be added up. I can furnish the information to the hon. Member later on.

As far as the question of new projects for Madhya Pradesh is concerned, we are going to take up about

41 he wprojects during the Eighth Five-Year Plan. We are going to take up 41 new projects with a capacity of 25-20 million tonnes and the investment will be approximately Rs. 2.000 crores

श्री सरेश पचीरी: मान्यवर, सरकार ने गल्फ बार के समय यह निर्णय लिया था कि स्माल कश्यमर्थ को कायला प्रदान किया जाएगा । अभी सरकार ने अपने उत्तर में स्वीकारा है कि घरेल उपभोक्ताओं को कोयला ब्रापृति में कमी रही। इसलिए मेरा ऐसा सुझाव है कि इसे दूर करने के लिए व्ह ँ अरूरी है कि स्टाक यार्ड नए बनाए जाये श्रीर जो श्रभी एमजीस्टिंग स्टाक यार्ड हैं उनको ज्यादा कोयला प्रदान किया जाए , इस संबंध में में माननीय मंत्री महादेश से यह जानकारी लेना चाहंगा कि मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर स्टाक यार्ड छोलने का प्रस्ताव है ताकि कंज्युमर्स को कोगला उपलब्ध कराम जा सके।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी हे यह जानकारी चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर स्टाक याडमी खोलने का प्रस्ताव है ताकि कंज्यमर्स को कोयला रक्तका कराण जा सके ? साथ ही महा धदेश में जो पावर स्टेशंस है जनमें कोणले की जितनी प्रावश्यकता थी, उस प्रावश्य-कता के दिवरीत जितना कोयला श्रमी तक प्रदान किया गया है वह अहुत कम है जैसा कि भापने अपने चार्ट में प्रदेशित किए। 🛊 । क्याः उस कमी को दूर करने के लिए आपकी तरफ मे प्रगत किए जायेंगें ? साब ही क्या रेलवे विभाग की तरफ हे श्रापको सहयोग प्रदान किया जा रहा है ? मध्य प्रवेश में बेगंस बढ़ाने के लिए क्या मध्य प्रदेश सरकार ने और कोंग्ला विभाग ने रेलवे को कोई अनुशंसा की है और रेल विभाग का इस संबंध में न्या शिकाई है ? मैं इन बातों की जानकारी **भंजी** मक्षेत्रक से चाहसा हं ।

SHRI P. A. SANGMA: Sir, there are 50 stockyards existing all over the country out of which 4 are in Madhya Pradesh. We realise the need of opening new stockyards in order to make coal available to the consumers—particularly domestic consumers. We have plans to open new stockyards but railways have expressed their difficulties of moving call to the stockyards. We are trying to negotiate with them. We are going to open about 20 new stockyards out of which 2 will be in Madhya Pradesh (Interruptions). I think within six months' time we should be able to finalise that.

As far as power sector is concern-end, Madhya Pradesh has got six thermal power stations. Out of these six power stations the problem is confined to one particular power house, which is Satpura power station. (Interruptions). More acute problem is in Satpura power station, the reason being that when this power station was sanctioned there was the presumption that there will be enough coal available in that area. But unfortunately, we find now that the availability of coal is not to the extent it is required for the power project. requirement is 4 million tonnes and at the moment we are producing only 2.6 million tonnes. Therefore, there is need" to open new mines in the neighbouring places. We are at it. One project at Chhatarpur has already been sanctioned. We. are going to sanction one more project at Tawa. So, there will be two more projects, one at Tawa and the other at Chhattarpur.

श्री राघव जो : माननीय समापति जी मध्य प्रदेश कांधल के स्थादन में एक प्रमुख प्रदेश हैं और उसके बावजद मी न तो मध्य प्रदेश के महस्पपूर्ण उद्योगों को कोयला मिल रहा है और न ही गैर महस्वपूर्ण रहोगों को कोणला मिल रहा है अभी भनानीए मंझी जी ने बसाया है कि है गैर महत्वपूर्ण उद्योगों को की 50 प्रतिकत लिक्ड क्वॉटिटी कोम्ला उपन्तम करायेंगे लेंकिन इन्होंने जो चार्ट प्रस्तुत क्रिया है उसके मुताबिक महाचपूर्ण उस्तेगा की भी किसी-किसी महीने में 50 परिवाद कोणला जपलक्ष नहीं कराणा गया है ! ग्रमरकंटक तापीर विद्युत गृह को जुन 1991 में

12-0 हजार टल कोण्ये की शाक्यकता थी जब कि उसे केंकल 47 हजार उन कोगला उपलब्ध कराण गण है। तो जब महत्त्वपूर्ण उद्योगों को ही शाप प्यप्ति कोण्या नहीं वे पा रहे हैं तो कर-महत्वपूर्ण उद्योगों को कब दे देना शुरू करेंगे? शाप ने इस संबंध में इस्ट्रम्शंस कब जारी की हैं और वर्तमान में 50 प्रतिशत के स्थान पर कितना कोण्या गैर-महत्वपूर्ण उद्योगों को प्रदान किया जा रहा है, गह माननीय मंत्री जी की जानना स्रहता है।

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I have had an occasion to inform this hon. House earlier that the non-core sector was really facing shortage of coal because the policy of the Government was to meet 100 per cent requirement of the core sector. When I reviewed the whole situation it was found that it was not justified, the non-core sector was being denied the coal. Therefore, on 18th of the last month we have taken a decision that 50 per cent of tha requirement of the noncore sector must be met immediately. The railways were very kind to provide us with the required number of wagons. Of course, the policy is to supply that coal either by rail or. by road. I am aware that 50 per cent is not enough, but I think that will help them to a great extent. In fact, there was a time when I was receiving, almost 50 to 100 letters and petitions every day but after having taken this decision of meeting, 50 per cent of the requirements of coal-I' am happy to inform the House-the number of complaints that I was receiving has been reduced to a great extent. I know it is not enough, but. we will try to improve our performance.

श्री श्रवीत जोगी: समापति महोदय,
यह बड़ी विडवना है कि देश में सबसे
श्रीवक कोयसा उत्पादम करने काला
प्रदेश हीने के बावजूद मध्य प्रदेश के ही
पादर प्लांटस तथा मध्य प्रदेश के ही
कारखानों को कोयसा नहीं मिस पा रहा
है। मैं केवल दो विश्वकों पर संबीजी से

उत्तर चाहता हूं। एक तो यह कि जो यह किसियस सिकल है जिसमें कभी कीस्ताः खदान चालें, कभी रेल मर्तालय कालें, कभी रेल मर्तालय कालें, कभी पावर प्लांट वाले एक दूसरे पर दोधारोकण करते रहते हैं भीर उनसे आपस में कोई समन्वय नहीं हो पाता। केवल अधिकारियों के लेवल पर आप समन्वय करने की कोशिश करते हैं। तो क्या परिस्थित को सुधारने के लिए कोई कदम उद्याएंगे कि राजनीतिक स्तर पर, मित्रयों के स्तर पर भी इन तीनों एजेंसिस्यों में कोशांडिनेशन हो, समन्वय हो जिससे परिस्थित में सुधार आए।

में यह भी जानना चाहूगा कि जो शापने लिकेज की नीति बनाई है उसमें जहां कोयला होता है उसके पास के पावर प्लांटस को उस क्षेत्र से कोयला न देकर दूसरें से देते हैं तो क्या कम से कम मध्य प्रदेश जैसे स्टेट के लिए जहां शादिवाली, उजड़ते हैं, जमल उजड़ते हैं तब कोयला निकलता है, तो वहां के लिए शाप लिकेज की नीति पर कोई शाधार भूत, सामूल सुधार लाने की कोशिश करेगे ?

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I can assure the House that there is perfect understanding between the various Ministries, both at officers' level and Ministers' level. In fact, myself, the Railway Minister and the Steel Minister have been meeting quite reguiarly and we are trying, to coordinate our functioning;

SHRI AJIT P. K. JOGI: Make it a formal plan so that the three or four Ministers should sit and coordinate

SHRI P: A. SANGMA: We are meeting this week again and we will try to formalize it; make it a permanent affair. As far as the movement is concerned, I do agree with. the honourable Member that the coal that is being produced in Madhya Pradesh is not made available 100 per cent there. It is hot possible because we have to take the-national economy in totality, and, therefore, we have to move the coal of Madfaya

श्री चत्रानन मिश्रः सभापित महोदय लिकेज सिस्टम रहने से बहुन असिनी होती हैं। मैं गली महोदय से जानना चाहुगा कि लकेज सिस्टम में जिस किसी कोइलरी ने डिफॉल्ट किया एक पटिकुलर पावर प्लांट को कोयला देने के बारे में उसके बारे में कोई जांच कर्याई है या नहीं? यदि कारवाई है तो जो दोवी हैं उनके असर भी कुछ कार्यवाही करेंगे?

Have you taken any action against those who have defaulted in giving coal to those particular power prp-jects? Was it not their duty to inform the Ministry or Coal India that this was going to happen? This is my question.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, actually, we have information we monitor it on a day-to-day basis. We have a monitoring system about the requirement of coal, availability of coal, despatches and stock position of every thermal plant and every steel plant every day. But we have problems of movement. Mishraji knows very well that in spite of the fact that coal is available, movement becomes difficult because of many reasons. As I said, we are now trying to coordinate our functioning, and we will coordinate it.

श्री नरेंस पुगिलया: मंत्री महोदय ने प्रभी बताया कि कोल को शोटेंज थ्रू आउट कंटरी में है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनके बुक-स्टाक में कितने मिलियन टन कीयला अवेलेबल है और उसके बाद कोल की शोटेंज क्यों है इस ही जांत्रे पालियामेंटरी कंसलटेटिय कमेटी को भज कर करायेंगे ?

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I did not say that there is shortage . of coal. In fact, coal is available. As of today our stock position' is about 35 million tonnes. I am talking about the availability at the consumption point. The non-availability at the consumption point is not because coal is not available but because we have constraints of movement. That is the reason.

## Subsidy on Cooking Gas

# \*4. SHRI SOM PAL:† SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

- (a) what is the element of subsidy per cooking gas cylinder and what is the break up of inputs in gas cylinder; and
- (b) whether private enterprises or Municipalities (have offered to lay the pipeline for supplying cooking gas to Ahmedabad, Kalal and Mehasana; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Actual subsidy depends on various factors *viz.* costs of production in different units, volume and prices of imported LPG, bottling costs, transportation costs etc. The average subsidy per cylinder during 1991-92 is estimated to . be about Rs. 60.00.

(b) Yes, Sir. Gas has not been allocated for supply to these towns since enough gas is not availably.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

<sup>†</sup>The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sompal.